रेलवे में समूह "घ" कर्मचारियों की अवैध भर्ती

4802. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में रेलवे के विभिन्न मंडलों में समूह "घ" के कर्मचारियों की भर्ती दुर्भावना से और अवैध तरीके से की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयवार इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी भर्ती के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क), (ख) और (घ) ग्रुप "डी" के कर्मचारियों की अनियमित भर्ती के कुछ मामले नोटिस में आये हैं रेलवेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) **मध्य रेलवे** : जाली दस्तावेजों के आधार पर 9 व्यक्तियों की अनियमित भर्ती का एक मामला पकड़ा गया था, इन व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया गया था और जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ।

(ii) **पूर्व रेलवे** : कुछ व्यक्तियों की जालसाजी से नियुक्ति का एक मामला नोटिस में आया है ।

(iii) **उत्तर रेलवे** : 14 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें ग्रुप "डी" कर्मचारियों के अनियमित भर्ती का आरोप लगाया गया जिनमें से 11 शिकायतों के मामले में छान-बीन का काम पूरा हो गया है । इन मामलों में कोई अनियमितता नहीं पायी गई है यदि अनियमित भर्ती के मामले नोटिस में आते हैं तो उन व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया जाता है और जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है ।

(iv) **पूर्वोत्तर सीमा रेलवे** : ग्रुप "डी" के 13 कर्मचारियों की अनियमित भर्ती का एक मामला पकड़ा गया था । उन कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया तथा संबंधित कर्मचारियों को भी सेवा से हटा दिया गया था ।

(v) **दक्षिण रेलवे** : ग्रुप "डी" कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं के दो मामले पकड़े गये हैं जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ।

(vi) **दक्षिण पूर्व रेलवे** : अनियमित भर्ती की 5 शिकायतों में से एक मामला प्रमाणित हो गया है और जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है ।

(ग) रेलों पर ग्रुप "डी" पदों पर सीधी भर्ती से संबंधित मौजूदा नीति भारतीय रेल स्थापना नियमावली में यथा अंतर्विष्ट भर्ती नियमों में दी गई है, जिसमें भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती की समयावधि, भर्ती यूनिट, आयु सीमा का मानदण्ड आदि से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित है ।

Conversion of Railway line between Madurai and Quilon

4803. SHRI V. GOPALSAMY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) what is the distance between Madurai and Quilon (metre gauge);

(b) whether the conversion from metre gauge to broad gauge has been started, if so, when and if not, the reasons therefor;

(c) what is the estimated cost of the whole project;

(d) as on date, how much funds have been spent on the whole project; and

(e) by when the whole line would be converted into broad gauge ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHRIEF) : (a) 268 kms.

(b) Madurai-Virudhunagar is already BG. Conversion of Virudhunagar-Quilon is not yet a sanctioned work.

(c) to (e) Do not arise.

Engine Shed at Katihar

4804. SHRI NARESH YADAV :
SHRIMATI KAMLA SINHA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 109 acres of land has been acquired for an Engine Shed at Katihar; and

(b) if so, by when the Engine Shed would become functional with details thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Conversion of Katihar Jogbani Railway Line

4805. SHRI NARESH YADAV :
SHRIMATI KAMLA SINHA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Jogbani Railway line is a MG line;

(b) whether it is also a fact that Jogbani is the Railway Station for Birat Nagar (Nepal) as such it has international importance;

(c) if so, whether Government are goir to convert this route from MG line to BG line on a priority basis; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. It is also a terminal station on Katihar-Jogbani MG section in Indian territory.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Privatisation of ancillary services in Railways

4806. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to privatise a number of ancillary services in various railway stations;

(b) if so, the details of these services and the time by when these are likely to be privatised;

(c) the estimate of savings as a result of privatisation;

(d) the criteria to be adopted to select private enterprise in this regard; and

(e) the number of workers likely to be affected and the mode of use of services of those likely to be rendered surplus as a result of the same ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF) : (a) Yes, Sir.

(b) A scheme of beautification-cum-maintenance of Bandra Station in lieu of sole advertisement rights at specified sites by an advertiser has been started. This has been extended to a few more stations over Indian Railways.

(c) The scheme has been introduced recently. No assessment of saving in expenditure as a result of privatisation has yet been made.

(d) Contract at Bandra Station was finalised on single tender basis on experimental basis. At other stations the same is finalised by calling the tenders.

(e) No staff will be rendered surplus on account of introduction of the above scheme.